इकाई 14 राष्ट्रीय आय का मापन

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य
14.1 प्रस्तावना
14.2 राष्ट्रीय आय
  14.2.1 राष्ट्रीय आय के मापन की विधियाँ
  14.2.2 उत्पादन विधि
  14.2.3 आय विधि
  14.2.4 व्यय विधि
  14.2.5 राष्ट्रीय आय के तीनों मानदण्डों का समंजन
14.3 भारत में राष्ट्रीय आय का मापन
  14.3.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के उपक्षेत्र
  14.3.2 कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त विधि
  14.3.3 पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त विधि
  14.3.4 निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त विधि
  14.3.5 भारत में राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ
14.4 सारांश
14.5 शब्दावली
14.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें
14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

14.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप समझ पाएँगे :

- राष्ट्रीय आय के मापन की माँग विधियाँ;
- राष्ट्रीय आय के तीन आयामों के घटक यानि उत्पादन, आय तथा व्यय के घटक;
- राष्ट्रीय आय के मापन हेतू भारतीय अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण;
- उपरोक्त सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों का प्रयोग; तथा
- भारत में राष्ट्रीय आय के मापन के कार्य में समस्याएँ और कठिनाइयाँ।

14.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय आय एक महत्त्वपूर्ण समष्टिगत आर्थिक समूह है। कुछ योग्यताओं के साथ इसे आर्थिक उत्पादन, आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास तथा आर्थिक कल्याण का द्योतक समझा जा सकता है। इस प्रकार इसके मापन का अत्यधिक महत्त्व है। राष्ट्रीय आय सही मापन न होने के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस इकाई के एक बड़े भाग में हम किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के मापन की विधियों का वर्णन करेंगे।

14.2 राष्ट्रीय आय

उत्पादन के प्रवाह, आय के सृजन तथा व्यय की अवधारणाओं का परिचय पहले ही इकाई 13 में किया गया है। यह भी बताया गया कि किस प्रकार से उत्पादन का प्रवाह आय का सृजन करता है जो तदनुसार व्यय के प्रवाह का कारण बनता है। व्यय का प्रवाह

पुनः उत्पादन के प्रवाह को जन्म देता है और इस प्रकार से उत्पादन, आय सृजन तथा व्यय की प्रक्रिया निरंतर एक के बाद दूसरे काल में अनवरत चलती रहती है। अर्थव्यवस्था के सामान्य निवासियों के संदर्भ में इन तीन प्रवाहों का मापन, हमें राष्ट्रीय आय में मापन की तीन विधियाँ प्रदान करता है।

14.2.1 राष्ट्रीय आय के मापन की विधियाँ

राष्ट्रीय आय के मापन की तीन विधियाँ हैं :

1) उत्पादन विधि अथवा मूल्य वृद्धि विधि

2) आय विधि

3) व्यय विधि

तीनों में से प्रत्येक विधि अर्थव्यवस्था में एक प्रवाह से संबंधित है। वास्तव में ये तीन विधियाँ राष्ट्रीय आय को देखने के तीन दृष्टिकोण है। इन तीनों विधियों में से प्रत्येक में प्रयुक्त सांख्यिकी आँकड़े तथा उपकरण भिन्न-भिन्न है, लेकिन अवधारणात्मक रूप से इन तीनों विधियों से मापित राष्ट्रीय आय का मूल्य एक ही होगा। यदि ये विधियाँ, मूलतः राष्ट्रीय आय का एक मूल्य नहीं देतीं तो ऐसा राष्ट्रीय आय के मापन के लिए आँकड़ों की कमी के कारण होगा। इन तीनों विधियों में से प्रत्येक में राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाली कठिनाइयाँ काफी भिन्न हैं।

14.2.2 उत्पादन विधि

किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उत्पादन विधि के प्रयोग के लिए मूलतः तीन चरण हैं। वे इस प्रकार है :

1) उत्पादक उद्यमों की सही पहचान करना और उनका औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकरण करना।

2) एक अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्र में प्रत्येक उत्पादक उद्यम तथा प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का मापन तथा सभी औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि को जमा करते हुए शुद्ध उत्पाद प्राप्त करना।

3) विदेशों से शुद्ध साधन आय मापन जिसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जमा करते हैं : अर्थव्यवस्था के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानि राष्ट्रीय आय को प्राप्त करना।

औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण

मोटे तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है :

क) प्राथमिक क्षेत्र

ख) द्वितीयक क्षेत्र

ग) तश्तीयक अथवा सेवा क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र

इसमें कृषि तथा संबंधित कार्यों वन, मत्स्य आखेट, खनन् तथा उत्खनन् को सम्मिलित किया जाता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर उत्पादन करता है। इसमें कोयला, लोह अयस्क तथा अन्य खनिजों का उत्पादन होता है। भारत में प्राथमिक क्षेत्र को तीन

भागों में विभाजित किया जाता है : (i) कृषि, (ii) वानिकी एवं लट्ठा बनाना, (iii) मत्स्यन तथा (iv) खनन् एवं उत्खनन्।

द्वितीयक क्षेत्र

इसमें विनिर्माण क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जहाँ एक प्रकार के उत्पाद का दूसरे प्रकार के उत्पाद में परिवर्तन होता है। भारत में द्वितीयक क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है :

(i) पंजीकृत विनिर्माण; (ii) ग़ैर पंजीकृत विनिर्माण; (iii) विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति।

तृतीयक क्षेत्र

इसमें सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाना है क्योंकि इस क्षेत्र उद्यमों के द्वारा मात्र सेवाएँ ही उत्पादित की जाती हैं। भारत में इस क्षेत्र में शामिल हैं : (i) रेलवे, (ii) अन्य साधनों द्वारा परिवहन तथा भंडारण, (iii) संचार, (iv) व्यापार होटल तथा जलपान गृह, (v) बैंकिंग तथा बीमा, (vi) स्थावर संपदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ, (vii) लोक प्रशासन तथा रक्षा तथा (viii) अन्य सेवाएँ।

शुद्ध मूल्य वृद्धि का मापन

एक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पहचान के बाद, अगला कदम है, प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र के द्वारा मूल्य वृद्धि का मापन। एक उत्पादन मूल्य तथा मध्यवर्ती आगतों की लागत का अंतर मूल्य वृद्धि कहलाता है।

आइए, अब हम मूल्य वृद्धि की अवधारणा को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि एक उत्पादक इकाई 'X' है जो एक वर्ष में 48000 रुपये की वस्तुओं की बिक्री करती है तथा वस्तुओं के भण्डार में 2100 रुपये की वृद्धि करती है। इस प्रकार से इस उत्पादक इकाई 'X' के उत्पादन का मूल्य है 50,000 रुपये है (48000 रुपये + 2000 रुपये)। मान लीजिए कि यह उत्पादक इकाई 'X' अर्थव्यवस्था की अन्य उत्पादक इकाइयों से 7000 रुपये का कच्चा माल तथा सेवाएँ खरीदतें हैं। हम समझते हैं कि 'X' द्वारा मूल्य वृद्धि को, उत्पादन के मूल्य में से अन्य उत्पादक इकाइयों से प्राप्त कच्चे माल तथा सेवाओं के मूल्य घटाकर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से इस वर्ष में इस उत्पादक इकाई 'X' द्वारा मूल्य वृद्धि 43000 रुपये (यानि 50,000 रुपये 7000 रुपये) होगी। एक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद, उस अर्थव्यवस्था की घरेलू क्षेत्र की सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा मूल्य वृद्धि को जमा करके प्राप्त किया जाता है। मूल्य वृद्धि की यह अवधारणा को एक अन्य उदाहरण द्वारा भी समझाई जा सकती है।

मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में केवल तीन उत्पादक इकाइयाँ हैं :

(क) वृक्ष काटने में संलग्न एक उद्यम, (ख) पहले उद्यम द्वारा काटे गए वृक्षों का लट्ठों में परिवर्तित करने के कार्य में संलग्न एक उद्यम, (ग) दूसरे उद्यम द्वारा उत्पादित लट्ठों से मेज बनाने के कार्य में संलग्न एक उद्यम। माना कि पहले उद्यम को वृक्ष काटने के कार्य में किसी भी प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से उपरोक्त तीन उद्यमों द्वारा एक वर्ष में मूल्य वृद्धि के व उत्पादन मूल्य को निम्न तालिका संख्या 14.2.2.1 की सहायता से दिखाया जा सकता है।

तालिका 14.2.2.1 उद्यमों द्वारा मूल्य वृद्धि

उद्यम	उत्पादित उत्पाद	उत्पादन का मूल्य (000 रुपयों में)	मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य (000 रुपयों में)	मूल्य वृद्धि (000 रुपयों में)
1.	लकड़ी	50	शून्य	50
2.	लट्ठे	80	50	30
3.	मेजें	150	80	70
	कुल	**280**	**130**	**150**

तालिका 14.2.2.1 से स्पष्ट है कि (वृक्ष काटने से) उत्पादित लकड़ी का मूल्य 50,000 रुपये है और दूसरे उद्यम के द्वारा उस लकड़ी से बने लट्ठों का मूल्य 80,000 रुपये है और लट्ठों से बनी मेजों का मूल्य 150,000 रुपये है। इन तीनों उद्यमों के द्वारा कुल उत्पादन (150,000 रुपये) है। इसे सकल घरेलू उत्पाद नहीं कहा जा सकता क्यों इसमें दो बार दोहरी गणना हुई है। एक लकड़ी के मूल्य की लट्ठों के मूल्य में दूसरे लट्ठों के मूल्य की मेजों के मूल्य में। इस दोहरी गणना से बचने के दो उपाय हैं– (क) केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य लेना और कच्चे माल आदि उत्पादों के मूल्यों को छोड़कर यह विधि अपनाना कठिन है क्योंकि यह निर्णय करना कि कौन-सा उत्पाद कच्चामाल है और कौन-सा अंतिम उत्पाद है, एक कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए यदि लकड़ी का उपयोग लट्ठे बनाने के लिए हों तो वह कच्चामाल मानी जाएगी और यदि इसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए तो इसे अंतिम उत्पाद माना जाएगा। इसलिए सकल घरेलू उत्पाद में दोहरी गणना से बचने के लिए इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता। उपरोक्त उदाहरण में तीसरे उद्यम के उत्पादन का मूल्य यानि 150,000 रुपये ही सकल घरेलू उत्पाद है जो कि अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद है। पहली और दोनों विधियों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 150,000 रुपये प्राप्त होता है। पहली विधि की अपेक्षा दूसरी विधि को अपनाना आसान है। यही कारण है कि एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद अथवा राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पादन विधि को मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है।

इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि :

i) समस्त उत्पादक द्वारा बाज़ार पर सकल मूल्य वृद्धि का योग हमें बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्रदान करता है;

ii) साधन लागत पर मूल्य वृद्धि का योग हमें साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्रदान करता है;

iii) साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें साधन लागत पर अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा शुद्ध मूल्य वृद्धि के योग से प्राप्त होता है।

विदेशों से शुद्ध साधन आय :

विदेशों से शुद्ध साधन आय की अवधारणा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ने से ही हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इसमें शामिल है :

1) विदेशों से प्राप्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक (शुद्ध);

2) सम्पत्ति एवं उद्यम से प्राप्त निबल आय;

3) विदेशों में निवासी निगमों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय का शुद्ध अवितरित अंश।

कर्मचारियों को विदेशों से प्राप्त पारिश्रमिक (शुद्ध)

इसका अनुमान हमें अपने विदेशों में कार्य कर रहे निवासियों को (जो अस्थायी रूप से देश से बाहर हों) मिली आमदनी में से अपने देश में कार्यरत अनिवासियों को किए गए भुगतान को घटाकर प्राप्त होता है। अस्थायी रूप से विदेशों में कार्य करने से हमारा अभिप्राय उन्हीं निवासियों से है जो एक वर्ष से कम अवधि के लिए देश से बाहर कार्य कर रहे हों। यदि वे एक वर्ष से अधिक समय किसी अन्य देश में कार्य करते हैं तो उन्हें वहाँ का निवासी माना जाता है तथा उनकी आय उनके कार्य क्षेत्र देश की राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। हाँ, यदि वह अपने परिजनों को कुछ धनराशि आदि भेजते हैं तो उसे हम विदेशों से प्राप्त चालू खाते के अन्तरणों में शामिल कर लेते हैं। पर ऐसे अन्तरण राष्ट्रीय आय का घटक नहीं कहलाते हैं। अतः कर्मचारियों को प्राप्त शुद्ध पारिश्रमिक धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है।

विदेशों में संपत्ति एवं उद्यम से प्राप्त शुद्ध आय

हमारे देश के निवासी उत्पादकों द्वारा विदेशों से प्राप्त ब्याज भाड़ा लाभांश तथा लाभ में से इन मदों में से अनिवासियों को किए गए भुगतान घटाकर हमें विदेशी संपत्ति एवं उद्यम से प्राप्त शुद्ध आय के आँकड़े मिलते हैं। इसमें सरकार को विदेशी ऋणों से प्राप्त शुद्ध ब्याज भी शामिल रहता है।

निवासी के निगमों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय का अंश

यह राशि हमारी उन कंपनियों की विदेशी उत्पादक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का अवितरित अंश है जो किसी अन्य देश में कार्य कर रही है। यह अवितरित लाभ सामान्यतः पुनः निवेश आदि के काम लाया जाता है। इसी प्रकार विदेशी कंपनियाँ और उनकी शाखाएँ भी अपने कार्य क्षेत्र के देशों में अर्जित लाभ का एक हिस्सा बचा रखती हैं। अतः इस मद में शुद्ध राशि विदेशों में कार्य कर रही हमारी कंपनियों/शाखाओं के अवितरित लाभ में से भारत में काम रही विदेशी कंपनियों के द्वारा इसी प्रकार बचाकर रखी गई राशियों का अन्तर ही शामिल होता है।

इस प्रकार से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होगी = विदेशों से कर्मचारियों को प्राप्य शुद्ध पारिश्रमिक जमा विदेशों से संपत्ति एवं उद्यम प्राप्ति जमा हमारी कंपनियों द्वारा विदेशों में बचाकर रखी गई अवितरित राशि।

विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अनुमान प्रयोग कर हम बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय, उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाज़ार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) का प्राक्कलन करते हैं। तथा

क) बाज़ार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद + विदेशों से शुद्ध साधन = बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय

ख) साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद + विदेशों से शुद्ध साधन आय = साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद

ग) बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद + विदेशों से शुद्ध साधन आय = बाज़ार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

घ) साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद + विदेशों से शुद्ध साधन आय = साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय)

सामान्यतः हम पहले घरेलू उत्पाद के सकल या शुद्ध बाज़ार कीमत या साधन लागत अनुमान पहले आकलित करते हैं। फिर इनमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर ही राष्ट्रीय आय के तदनुरूप अनुमान तैयार किए जाते हैं।

किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय का उत्पादन विधि से अनुमान लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :

किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय का उत्पादन विधि से अनुमान लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :

1) अपने सहयोग के लिए उत्पादित सामग्री उत्पादन में जोड़नी चाहिए। अतः भौतिक उत्पादन को बाज़ार कीमत से गुणाकर स्वयं उपयुक्त सामग्री के मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

2) अपने निवास के काम आ रहे भवनों के भाड़े का अनुमान लगाकर उन भवनों की सेवाओं को राष्ट्रीय उत्पादन में जोड़ा जाता है।

3) सरकार, निजी उद्यमों तथा गृहस्थों के लिए उत्पादित वस्तुओं आदि का मूल्य भी अनुमानित किया जाना आवश्यक है।

4) पुरानी वस्तुओं के क्रय-विक्रय से राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती पर यदि इस विनिमय में किसी की दलाली मिलती है तो उस दलाली की रकम को दलाल की सेवाओं के मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय में जोड़ना आवश्यक हो जाता है। दलालों की सेवाओं का मूल्य उन्हें प्राप्त कमीशन या दलाली से अनुमानित होता है।

14.2.3 आय विधि

किसी उत्पादन इकाई द्वारा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि उस इकाई में सृजित साधन आय अर्थात् कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष तथा स्वनियोजितों की मिश्रित आय, के समान होती है। अतः किसी उत्पादक इकाई का योगदान ज्ञात करने के लिए हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष व मिश्रित आय को जोड़ लेते हैं। यदि अर्थव्यवस्था की कमी सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा सृजित साधन आय जोड़ ली जाए तो हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद की साधन लागत ज्ञात हो जाती है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय जान सकते हैं।

साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास का प्रावधान जोड़कर हमें साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन ज्ञात होता है। इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की राशि जोड़ने पर हमें बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है।

इसी तरह साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा मूल्यह्रास प्रावधान का योग हमें साधन लागत पर घरेलू उत्पाद देता है।

आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन कुछ इस प्रकार होता है :

1) पहले साधन सेवाएँ प्रयोग करने वाली उत्पादक इकाइयों की पहचान की जाती है;

2) विभिन्न साधन-भुगतानों का वर्गीकरण किया जाता है;

3) साधन भुगतान के घटकों का अनुमान लगाया जाता है;

4) विदेशों से प्राप्त साधन आय का अनुमान लगाते हैं। इसी साधन लागत पर घरेलू उत्पाद

में जोड़कर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की साधन लागत अथवा राष्ट्रीय आय का अनुमान प्राप्त करते हैं।

उत्पादन विधि के लिए प्रयुक्त उत्पादक इकाइयों के वर्गीकरण का आय विधि के लिए भी प्रयोग हो सकता है।

साधन आयों को इन वर्गों में बाँटा जाता है :

क) कर्मचारियों का पारिश्रमिक

ख) किराया

ग) ब्याज,

घ) लाभ तथा

ङ) स्वनियोजितों की मिश्रित आय

साधन आय का मोटा-मोटा वर्गीकरण कुछ इस तरह से भी हो सकता है :

अ) कर्मचारियों का पारिश्रमिक

ब) प्रचालन अधिवेश तथा

स) स्वनियोजितों की मिश्रित आय।

आय विधि से राष्ट्रीय आय के आकलन में इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है :

1) साधन आय तथा हस्तांतरण का भेद अच्छी तरह समझना चाहिए। साधन आय उत्पादन के निमित्त प्रदत्त साधन सेवाओं के बदले में मिला प्रतिफल है पर हस्तांतरण आय किसी तरह के साधन प्रयास के बिना ही मिली प्राप्ति है। केवल साधन आय ही राष्ट्रीय आय है। हस्तांतरण को हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते।

2) स्वयं निवास के लिए प्रयुक्त भवनों का भाड़ा भी आँका जाता है। इस आकलित राशि में से रख-रखाव पर आया खर्च घटाकर शेष रकम उत्पादन विधि की ही भाँति राष्ट्रीय आय में जोड़ दी जाती है।

3) तस्करी, जुआ तथा लाटरी आदि से हुई अनायास प्राप्ति को भी हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते।

4) पुरानी चीज़ों के विनिमय से भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय अप्रभावित रहती है। इनकी बिक्री से प्राप्त राशि किसी साधन सेवा का प्रतिफल नहीं होती, अतः उसे राष्ट्रीय आय में स्थान भी नहीं मिलता।

14.2.4 व्यय विधि

उत्पादन की प्रक्रिया में सृजित आय उत्पादक साधनों को प्राप्त होती है। इन प्राप्तियों को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं : (क) कार्य के प्रतिफल स्वरूप प्राप्ति तथा (ख) सम्पत्ति के स्वामित्व और उद्यमवृत्ति से प्राप्ति। कार्य से प्राप्ति का लाभ श्रमिकों को प्राप्त होता है तथा पूँजी व उद्यम से प्राप्त आय उनके स्वामी प्रयोग करते हैं। भू-स्वामी भी यहाँ उद्यमी ही माने जाते हैं। उत्पादक साधन अपनी आय को या तो चालू उत्पादन में से उपभोग के विभिन्न खर्च कर सकते हैं या फिर वे इसका एक अंश बचाकर भी रख सकते हैं। इन बचतों से पूँजी का भण्डार समृद्ध होता है—यही निवेश है। यदि सभी इकाइयों (शेष

विश्व सहित) के अन्तिम उपभोग व्यय तथा सकल निवेश को जोड़ा जाए तो हमें बाज़ार कीमतों पर अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। इसी बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास तथा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाकर साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के आँकड़े मिलते हैं। इनमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ने से हमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय का अनुमान प्राप्त हो जाता है। बाज़ार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की घटक व्यय मदें इस प्रकार हैं :

1) निजी अंतिम उपभोग व्यय,

2) सरकारी का अंतिम उपभोग व्यय,

3) सकल घरेलू स्थिर पूँजी निर्माण,

4) स्टॉक में वशद्धि

5) वस्तुओं और सेवाओ का शुद्ध निर्यात।

निजी अंतिम उपभोग व्यय

घरेलू बाज़ार में निवासी तथा अनिवासी परिवारों द्वारा चालू खाते के व्यय को ही निजी क्षेत्र का अंतिम उपभोग व्यय माना जाता है। इसमें परिवारों को सेवा प्रदान कर रही पर लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का व्यय भी शामिल है। इस व्यय में नए टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल है। पर भूमि पर हुआ व्यय नहीं। साथ ही, पुरानी चीज़ों, रद्दी व कबाड़ की बिक्री से हुई प्राप्तियाँ भी इस व्यय से निकाल दी जाती हैं। यह अवधारणा अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमाओं में व्यय से जुड़ी है— यह राष्ट्रीय उत्पाद के विचार से कुछ दूर हट जाती हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे निवासियों द्वारा विदेशों से सीधी खरीदारी तथा अनिवासियों द्वारा हमारे देश में सीधी खरीदारी के आँकड़े एकत्र कर पाना सहज नहीं है। अतः केवल निवासियों के अंतिम उपभोग पर खर्च शामिल रहता है। हम स्वयं आवासित भवनों के किराए का भुगतान, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का अनुमान तथा खाना कपड़ा व रहने की जगह के रूप गृहस्थों द्वारा अपने नौकरों को किए गए गैरमौद्रिक भुगतानों का अनुमानित मूल्य भी जोड़ लेते हैं।

निजी अंतिम उपभोग के आकलन के लिए हमें दो प्रकार के आँकड़ों की जरूरत पड़ती है : (क) बाज़ार में बिक्री हुई कुल मात्रा (ख) परिवारों द्वारा चुकाए गई खुदरा कीमतें। इस कुल मात्रा को खुदरा कीमतों द्वारा गुणा किया जाता है।

अपने उपभोग के लिए उत्पादन को उत्पादन का हिस्सा माना गया, वह आय का भी भाग है और उसका उपभोग तो होता ही है। अतः इस उत्पादन की मात्रा को भी बाज़ार में प्रचलित खुदरा कीमतों से गुणाकर मूल्य ज्ञात किया जाता। वे मकान जिससे मालिक स्वयं रहते हैं का संभावित किराया भी उत्पादन, आय तथा अंतिम उपभोग तीनों में जोड़ा जाता है।

सरकारी अंतिम उपभोग व्यय

सरकारी विभागों द्वारा अपनी सेवाएँ प्रदान करने हेतू खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओ के मूल्य में से इन सेवाओं की बिक्री की राशि घटाकर हमें सरकार का अंतिम उपभोग व्यय ज्ञात होता है। यहाँ हम बजट तथा गैरबजटीय संसाधनों ने वित्तीय सामान्य प्रशासन के उन सभी अवयवों और घटकों की बात कर रहे हैं और केन्द्र, राज्य या स्थानीय निकायो द्वारा संचालित होते हैं। सार्वजनिक उद्यमों और विभागीय उपक्रमों को हम इस श्रेणी से बाहर ही रखते हैं।

सरकार के अंतिम उपभोग का मूल्य सार्वजनिक प्रयोग के निमित्त स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा प्रतिरक्षा व कानून और व्यवस्था आदि के क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं के मूल्य के समान माना जाता है। इन सेवाओं की जनसामान्य को बिक्री नहीं की जाती, इसीलिए इनका मूल्यांकन इन पर आई लागत से ही होता है। इनकी लागत में ये खर्च शामिल किए जाते हैं :

क) मध्यवर्ती उपभोग

ख) कर्मचारियों का पारिश्रमिक

ग) सरकार द्वारा विदेशों में अपने दूतावासों आदि के प्रयोग के लिए प्रत्यक्ष खरीदारी तथा इनमें से

घ) सरकार द्वारा सेवाओं की पूर्ति से हुई प्राप्तियाँ घटा दी जाती है। इन प्राप्तियों के उदाहरणस्वरूप हम सरकारी अस्पतालों में गरीबों से प्राप्त परीक्षण शुल्क आदि तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्ति आदि को शामिल कर सकते हैं।

सकल घरेलू स्थिर पूँजी निर्माण

उद्योगों, सरकारी सेवा प्रदाताओं तथा परिवारों को सेवा देने वाली ग़ैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा नए टिकाऊ पदार्थों पर व्यय में से पुराने पदार्थों के विक्रय मूल्य घटाकर हमें सकल घरेलू स्थिर पूँजी निर्माण का मान प्राप्त होता है। इसमें रक्षा सेवाओं के साज-सामान पर आया सरकारी खर्च शामिल नहीं होता। भूमि की गुणवत्ता सुधारने पर तथा एक वर्ष से अधिक समय लगने वाले वन संवर्धन कार्यों को इस पूँजी निर्माण का अंग माना जाता है। इसी प्रकार परिवारों द्वारा गृहनिर्माण व्यय भी इसका हिस्सा है। इस सकल पूँजी निर्माण में घिसावट का अलग लेखा नहीं होता पर मूल्यह्रास का प्रावधान घटाकर हम शुद्ध स्थिर पूँजी निर्माण ज्ञात कर सकते हैं।

यह सकल पूँजी निर्माण का विचार देश की घरेलू सीमाओं से बँधा है। इसमें निवासी उद्योगों, राजकीय सेवाओं तथा परिवारों को सेवा प्रदान करने वाली ग़ैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा अधिग्रहित किए गए अचल परिसम्पत्ति भी शामिल है। भारत में संस्थागत आधार पर इस अचल पूँजी निर्माण का तीन श्रेणियों में विभाजन किया जाता है : सार्वजनिक, निजी एवं गृहस्थ क्षेत्र। दूसरी ओर, परिसम्पत्तियों के आधार पर यह निर्माण कार्यों तथा यंत्रों व उपकरणों में भी बाँटा जा सकता है। निर्माण कार्यों पर व्यय नए निर्माण पर निर्माण होने वाले व्ययों को जोड़कर या फिर इन पर लगने वाली आगतों के मूल्यों को जोड़कर जाना जा सकता है। ये सीमेंट, इस्पात ईंटें, लकड़ी तथा अन्यान्य उपस्करों के रूप में होते हैं। इन्हीं के साथ निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की मज़दूरी जोड़ना भी आवश्यक है, आगतों का मूल्य उनकी प्रयुक्त मात्रा तथा प्रति इकाई चुकाई गई कीमत के गुणन से प्राप्त होता है। इस प्रकार से निर्माण कार्य पर हुए व्यय के आकलन को वस्तु प्रवाह विधि कहा जाता है। आगतों के मूल्य में कर्मचारियों के प्रतिदान, ब्याज, भाड़ा व लाभ जोड़कर ही हम नए निर्माण का मूल्य ज्ञात कर पाते हैं। पुराने भवनों का व्यापक सुधार-बदलाव, उनमें नए कमरे जोड़ना, निर्माणाधीन भवन तथा अपने प्रयोग के निमित्त चल संपत्तियों का अधिग्रहण (उत्पादक क्षेत्रकों द्वारा) आदि को भी नव-निर्माण पर खर्च माना जाता है।

इसी प्रकार यंत्रों व उपकरणों पर अंतिम व्यय का मूल्यांकन उनकी मात्रा तथा खुदरा बाज़ार कीमतों के गुणन द्वारा होता है। उत्पादकों द्वारा आन्तरिक प्रयोग के लिए बनाई गई मशीनें आदि को भी इस व्यय में जोड़ा जाता है।

स्टॉक में परिवर्तन

स्टॉक में हम तैयार तथा कच्चा माल, निर्माणाधीन सामान (भवन नहीं) आदि को सम्मिलित करते हैं। खेतों में खड़ी फसलें और वनों में खड़े वृक्ष इसमें शामिल नहीं होते, पर वध

के लिए पाले गए पशु कटे हुए वृक्ष एवं काटी गई फसलें भण्डार का अंग होती हैं। इस प्रकार से स्टॉक में परिवर्तन हम उपरोक्त सभी मदों के वर्ष के आरंभ के मूल्यांकन की बजाय मूल्यांकन से तुलना द्वारा ज्ञात करते हैं।

स्टॉक का वर्गीकरण हम पदार्थों के स्वरूप और इनके स्वामियों की आर्थिक गतिविधियों के अनुसार किया जाता है। इसी तरह से हम वर्गीकरण में (क) नई उत्पादित और आयातित वस्तुओं का उनके निर्माता उद्योगवार वितरण, (ख) प्रकारानुसार पुरानी वस्तुओं तथा (ग) बेकार या नाक्कारा वस्तु आदि की श्रेणियाँ भी बना सकते हैं।

अन्ततः वस्तुओं/पदार्थों के भौतिक संग्रह में आए परिवर्तन को बाज़ार भावों से गुणा कर स्टॉक परिवर्तन का मूल्य किया जाता है।

वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात

यह वर्ष भर में देश से निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा देश में आयात मूल्य का अन्तर है। अतः राशि ऋणात्मक भी हो सकती है। इसका धनात्मक होना केवल यही दर्शाता है कि निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक थे। यदि आयात अपेक्षाकृत अधिक रहे हों तो यह शुद्ध राशि ऋणात्मक हो जाती है।

भारत में हम देशवासियों द्वारा वस्तुओं का स्वामित्व विदेशियों को सौंपने तथा उनके प्रति दी गई सेवाओं को निर्यात कहते हैं। देश की सीमाओं से बाहर गए निर्यात तो सीमाशुल्क अधिकारियों के खातों में भी दर्ज हो जाते हैं पर बाहरी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा हमारे देश की ही प्रयोग के लिए खरीदी गई वस्तुएँ भी निर्यात ही होती हैं। इनका मूल्यांकन हम F.O.B. अर्थात् बाहर जाने वाले बन्दरगाह तक का मूल्य जोड़कर करते हैं। इसके विपरीत विदेशों से प्राप्त की गई वस्तुओं और सेवाओं तथा अनिवासियों द्वारा भारतीयों के प्रति प्रदत्त सेवाओं के मूल्य जोड़कर हम कुल आयात का हिसाब लगाते हैं। सीमाशुल्क अधिकारी इन आयातों को देश की सीमा में प्रवेश के आधार पर दर्ज करते हैं। इनके साथ ही दूसरे देशों में ही प्रत्यक्षतः हासिल की गई वस्तुओं का मूल्य जोड़ लिया जाता है। मूल्यांकन का आधार हमारे देश की बन्दरगाह तक कुल लागत अर्थात् c.i.f. होता है। अर्थात् हम वस्तु की वास्तविक कीमत में बीमा तथा अन्तरराष्ट्रीय ढुलाई को जोड़कर कुल आयात कीमत को ही आयात का मूल्य मानते हैं।

अतः इस प्रकार से बाज़ार कीमत पर सकल घरेलु उत्पाद पर व्यय होगा : निजी अंतिम उपभोग व्यय **जमा** सरकारी अंतिम उपभोग व्यय **जमा** सकल पूँजी निर्माण **जमा** स्टॉक में वृद्धि शुद्ध निर्यात (अर्थात् वस्तु और सेवाओं के निर्यात मूल्य तथा उनके आयातों के मूल्य का अन्तर) बाज़ार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को हम उपर्युक्त सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाकर ज्ञात करते हैं। इसी तरह से साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का मान जानने के लिए हम बाज़ार कीमत पर घरेलू उत्पाद में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों (अर्थात् अप्रत्यक्ष कर घटा आर्थिक सहायता) की राशि घटा देते हैं। अतः साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (राष्ट्रीय आय) होगी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद **जमा** विदेशों से शुद्ध साधन आय।

कई बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद जानने के लिए अन्य घटकों के साथ हम निर्यात को क्यों जोड़ते हैं तथा आयात को क्यों घटा देते हैं। निर्यात को जोड़ने का कारण अधिक आसानी से समझ आ सकता है : यह घरेलू क्षेत्र के उत्पादन का वह हिस्सा है जिसे अनिवासी या विदेशी खरीद कर लेते हैं। अतः घरेलू उत्पादन के संपूर्ण आकलन में इसे जोड़ा जाना अस्वाभाविक नहीं होगा। दूसरी ओर हमारे देश के निवासियों अर्थात् गृहस्थों; कंपनियों तथा सरकार द्वारा क्रमशः निजी उपभोग, सकल स्थिर पूँजी निर्माण और सरकारी उपभोग के लिए किए गए खर्च में से हम विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर हुआ व्यय घटा है। अतः यह कहना भ्रामक होगा कि घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध

बाद हम तालिका 14.2 के अनुरूप प्रस्तुत कर सकते हैं।

तालिका 14.2 : राष्ट्रीय आय मापने की तीनों विधियों का समंजन

उत्पादन विधि	आय विधि	व्यय विधि
प्राथमिक क्षेत्र में साधन लागत पर मूल्य वृद्धि	कर्मचारियों का पारिश्रमिक	निजी अंतिम/उपभोग व्यय + सरकारी अंतिम उपभोग व्यय + सकल घरेलू स्थिर पूँजी निर्माण
+	+	+
द्वितीयक क्षेत्र में साधन लागत पर मूल्य वृद्धि	प्रचालन अधिशेष	भण्डार (स्टॉक) में परिवर्तन
+	+	+
तृतीयक क्षेत्र में साधन लागत पर मूल्य वृद्धि	स्वनियोजित की मिश्रित	आयवस्तुओं सेवाओं का शुद्ध निर्यात घटा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा पूँजी का मूल्यह्रास
+	+	+
शेष विश्व में शुद्ध साधन आय	शेष विश्व से शुद्ध साधन आय	शेष विश्व से शुद्ध साधन आय

बोध प्रश्न 1

1) इनमें भेद करें :

क) सकल तथा शुद्ध निवेश

.....

.....

.....

.....

ख) विदेशों से शुद्ध साधन आय तथा शुद्ध निर्यात

.....

.....

.....

.....

ग) सकल एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

.....

.....

.....

.....

घ) सकल एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद

.....

.....

.....

.....

2) विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटकों का निरूपण करें। इस मद से शुद्ध प्राप्ति ऋणात्मक भी हो सकती है? क्यों?

.....

.....

.....

.....

.....

3) निम्नांकित विधियों का प्रयोग कर बाज़ार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन के घटकों का ब्यौरा दें :

(क) उत्पादन विधि, (ख) आय विधि, (ग) व्यय विधि

.....

.....

.....

.....

.....

14.3 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन

हमारे देश में राष्ट्रीय आय आकलन उत्पादन, आय तथा विधियों के मिले-जुले प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर उनके लिए उपयुक्त विधि का चयन होता है। कृषि तथा विनिर्माण जैसे क्षेत्र को जहाँ भौतिक पदार्थों का उत्पादन होता है, उत्पाद विधि का प्रयोग करना सहज रहता है क्योंकि उत्पादन के आँकड़े आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र से आय के आँकड़े सहज सुलभ होते हैं। अतः वहाँ आय विधि का प्रयोग होता है। पर निर्माण क्षेत्र में तो उसके प्रकल्पों पर होने वाले व्यय के आँकड़ों का ही सहारा लेकर राष्ट्रीय आय में उसके योगदान का अनुमान किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान

भारत की आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय आय के अनुमान कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के व्यक्तिगत प्रयासों के परिणाम ही थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। उन्होंने सन् 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपये आँकी थी और प्रतिव्यक्ति आय का अनुमान मात्र 20 रुपये था। बाद में विलियम डिग्नी ने सन् 1897-98 में राष्ट्रीय आय 390 करोड़ रुपये आँकी पर इस बीच प्रतिव्यक्ति आय घटकर मात्र

17 रुपये रह गयी। फिंडले शिर्राज ने 1911 में कुल आय 1942 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय 80 रुपये बताई। जाने माने विशेषज्ञ डॉ. बी.के.आर.वी. राव ने 1925-29 की अवधि में (औसत) राष्ट्रीय आय 2301 करोड़ आँकी तथा उनका अनुमान था कि इस अवधि में प्रति व्यक्ति आय 78 रुपये रही। आर.सी. देसाई ने इन्हें 1930-31 में क्रमशः 2809 करोड़ तथा 72 रुपये आँका। ये सभी अनुमान बहुत महत्त्वपूर्ण तो थे पर इनमें अनेक त्रुटियाँ भी थी। एक तो ये बहुत सीमित आँकड़ों पर आधारित थे, दूसरे इनकी विधियाँ तथा आकलन के आधार क्षेत्र भी तुलनीय नहीं थे। किन्तु इन त्रुटियों के बाद भी ये अनुमान स्वतंत्रता पूर्व भारत की गरीबी तथा आर्थिक पिछड़े की झलक तो दिखा ही देते हैं।

स्वतंत्रता पश्चात् राष्ट्रीय आय का प्राक्कथन

सन् 1947 में आज़ादी के बाद से ही सरकारी तौर पर राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन का क्रम आरम्भ हुआ। 4 अगस्त 1949 को प्रो. पी.सी. महलनवीस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय प्राक्कलन समिति (National Income Committee) का गठन हुआ। प्रो. वी.के.आर.वी. राव तथा प्रो. डी.आर. गाडगिल इसके सदस्य थे। समिति की पहली रिर्पोट 1951 में तथा अंतिम रिर्पोट 1954 में आई। पहली रिर्पोट में समिति ने राष्ट्रीय आय के आकलन की अवधारण पृष्ठभूमि के निरूपण के साथ-साथ 1948-1949 के लिए राष्ट्रीय आय के अनुमान भी प्रस्तुत किए। अंतिम रिपोर्ट में उन्होंने 1948-49 व 1950-51 के चालू बाज़ार भावों व स्थिर (1948-49) भावों पर राष्ट्रीय आय के ताजा अनुमान भी प्रस्तुत किए। समिति ने राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए विधियों के सुझाव भी दिए।

सन् 1950 में इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Sarvey) की स्थापना की गई थी। इसे ही राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए नियमित आधार पर आँकड़े संग्रह करने का कार्य सौंपा गया था।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (C.S.O.)

वर्ष 1954 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना पर इसे राष्ट्रीय आय का संगठन सौंप दिया गया। इसने 1956 में अपना पहला श्वेत-पत्र जारी किया तथा उसके बाद से हर वर्ष यह राष्ट्रीय लेखा अनुमानों के नाम से राष्ट्रीय आय के वार्षिक अधिकृत आँकड़े प्रस्तुत करता आ रहा है। यह संगठन भारत सरकार के योजना मंत्रालय में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान चालू व स्थिर भावों पर अन्यान्य समष्टिगत् आँकड़ों के साथ तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय की विस्तृत विधि बताने के लिए यह संगठन समय-समय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी स्रोत एवं विधियाँ (National Income Statistics Sources and Methods) भी प्रकाशित करता रहा है। इसका अंतिम संस्करण फरवरी 1988 में छपा और इसके बाद अभी तक कोई संस्करण नहीं छपा।

अपनी स्थापना के बाद से केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने अभी तक वर्ष 1948-49, 1960-61, 1970-71 तथा 1980-81 की स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किए हैं। हाल ही में आधार वर्ष 1993-94 हो गया है। इन्हीं के अनुरूप पर राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं के अनुरूप चार राष्ट्रीय आय अनुमान शृंखलाएँ तैयार हुई हैं। ये हैं : (क) परंपरित शृंखला, (ख) संशोधित शृंखला, (ग) नई शृंखला तथा (घ) परंपरागत लेखा अनुमानों की नई शृंखला।

14.3.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के उपक्षेत्रक

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 उपक्षेत्रकों में विभाजित किया है। इनके अलावा एक चौदहवाँ क्षेत्रक भी है— बाह्य लेन-देन। ये क्षेत्रक इस प्रकार हैं :

1) कृषि, वानिकी तथा मत्स्यन

(क) कृषि, (ख) वानिकी एवं लट्ठा कटाई, (ग) मत्स्यन

2) खनन् एवं उत्खनन्

3) विनिर्माण

(क) पंजीकृत, (ख) अपंजीकृत

4) विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति

5) निर्माण

6) व्यापार, होटल एवं जलपानगश्ह

(क) व्यापार, (ख) होटल तथा जलपानगश्ह

7) परिवहन भण्डारण एवं संचार

(क) रेलवे, (ख) अन्य परिवहन, (ग) भण्डारण, (घ) संचार

8) वित्तीयन, बीमा, स्थावर संपदा एवं व्यावसायिक सेवाएँ

(क) बैंकिंग तथा बीमा, (ख) स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएँ

9) सामुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएँ

(क) सार्वनिक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, (ख) अन्य सेवाएँ।

राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए प्रयुक्त विधियाँ

राष्ट्रीय आय के आकलन की तीनों प्रमुख विधियों—उत्पादन आय तथा व्यय विधियों—पर हम पहले ही 14.2 में पर्याप्त विस्तार से विचार कर चुके हैं। सैद्धांतिक दशष्टि से यदि पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हों तो तीनों विधियों से स्तवंत्र रूप पर ही पहुँचेंगे। पर व्यावहारिक दशष्टि से अर्थव्यवस्था के सभी अवयवों पर एक ही विधि का प्रयोग कर राष्ट्रीय आय में इसके योगदान को मापना संभव नहीं हो पाता। सौभाग्यवश, इन विधियों को मिले-जुले प्रयोग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों के योगदान आकलन से भी काम चल जाता है। कहाँ किस विधि का प्रयोग होता है यह बात पर्याप्त एवं विश्वास योग्य आँकड़ों की उपलब्धि पर निर्भर है। भारत के घरेलू उत्पाद के अनुमान के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन उत्पादन, आय, व्यय तथा वस्तु प्रवाह विधियों के मिले-जुले प्रयोग का सहारा लेता है। आँकड़ों की उपलब्धि में सुधार के साथ-साथ उत्पादन विधि का प्रयोग कर रहे क्षेत्रकों में वृद्ध होती रही है।

आजकल इन क्षेत्रकों में उत्पादन विधि का अनुसरण होता है :

(1) कृषि, (2) वानिकी एवं लट्ठा बनाना, (3) मत्स्यन, (4) खनन् एवं उत्खनन् तथा, (5) पंजीकृत विनिर्माण

आय विधि का अनुसरण इन क्षेत्रकों में होता है :

(1) अपंजीकृत विनिर्माण, (2) विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, 3) परिवहन भण्डारण एवं संचार, (4) व्यापार होटल एवं जलपानगृह, (5) बैंकिंग व बीमा, (6) स्थावन सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवा, (7) लोक प्रशासन एवं रक्षा और (8) अन्य सेवाएँ।

निर्माण क्षेत्र में व्यय तथा वस्तु प्रवाह विधियों को मिलाकर उसका योगदान आँका जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यय तथा बाहरी तथा शहरी क्षेत्र के निर्माण कार्यों में वस्तु प्रवाह विधि प्रयोग होती है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त आँकड़े एकत्र कर बाज़ार भावों पर राष्ट्रीय आय से उनके योगदान का अनुमान लगाती है। मूल्यह्रास तथा जहाँ आवश्यक हो शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की राशियाँ ही हम सभी क्षेत्रकों द्वारा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू मूल्य वृद्धि मानते हैं। इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय का अनुमान प्राप्त होता है।

14.3.2 कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त विधि

कृषि एवं संबंधित कार्य

सरकारी सिंचाई परियोजनाओं को छोड़कर कृषि एवं उससे जुड़ी पशुपालन आदि जैसे सभी कार्यों का योगदान उत्पादन विधि द्वारा मापा जाता क्योंकि इन सभी में कुल उत्पादन का मूल्य, सहायक उत्पादनों व कच्चे माल आदि के मूल्यांकन एवं पूँजी के ह्रास का आकलन आदि के माध्यम से ही मूल्यवृद्धि का अनुमान संभव हो पाता है। सिंचाई में आय प्रवाह विधि का प्रयोग कर इस क्षेत्र का योगदान मापा जाता है। कृषि फसलों तथा पशुपालन के कुल उत्पादनों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाता है। पर मूल्य वृद्धि का अनुमान पूरे क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से ही लगाया जाता है।

प्रत्येक प्रमुख फसल के उत्पादन के अनुमान के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन (Random Sampling) विधि का सहारा लेते हैं। जहाँ-जहाँ सह फसल उगाई जाती है उन जिलों में कुछ खेत चुने जाते हैं। एक हैक्टर क्षेत्रफल की फसल की कटाई कराकर उत्पादन को उस जिले के उस मौसम के औसत थोक कीमत से गुणा किया जाता है। इस तरह से एक हैक्टर फसल का बाज़ार मूल्य पता लग जाता है। इसको जिले भर में जितने हैक्टर क्षेत्रफल में यह फसल लगी हो उसे गुणा कर जिले के उत्पादन का मूल्य प्राप्त होता है। किसी राज्य के सभी जिलों के उत्पादन का जोड़ उस राज्य के उत्पादन का योग बन जाता है। भारत में राज्य सरकार इस प्रकार के वार्षिक फसल-कटाई के यादृच्छिक प्रतिचयन 36 मुख्य फसलों के लिए करती है। अन्य छोटी-छोटी फसलों के उत्पादन का मूल्यांकन अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी से किया जाता है। पशुधन के उत्पादन जैसे दूध, एवं दूध उत्पाद, मांस तथा अंडों, मुर्गों का मूल्यांकन पूर्णगणना (Census) विधि द्वारा होता है।

कृषि तथा संबंधित कार्यों में मूल्य वृद्धि के अनुमान के लिए उत्पादन मूल्य में से आदानों की लागत के रूप में घटाएँ हैं : (क) बीजों का मूल्य, (ख) खाद, उर्वरक, (ग) यंत्रों तथा स्थायी संसाधनों की मुरम्मत तथा संचालन पर खर्च, (घ) पशुचारा, (च) सरकार को देय सिंचाई शुल्क, (छ) बाज़ार के खर्च, (ज) बिजली का खर्च, (झ) कीटनाशक आदि तथा (त) डीजल तेल पर हुआ खर्च।

कृषि क्षेत्र में इन परिसंपत्तियों के लिए पूँजीगत मूल्यह्रास का आकलन होता है।

क) कृषि यंत्र उपकरण एवं परिवहन संसाधन

ख) खेत में बने घर तथा पशुओं के बाड़े

ग) बाग व बगीचे

घ) बँधे तथा उच्च भूमि से जुड़े सुधार कार्य

ङ) कुएँ तथा सिंचाई के माध्यम

च) मांस आदि के विक्रय स्थल

इस क्षेत्र उत्पादन के कुल मूल्य से मूल्यहास घटाकर हम शुद्ध मूल्य ज्ञात करते हैं। सन् 1990-91 में भारत में कृषि क्षेत्र में मूल्य वृद्धि इस प्रकार रही :

कृषि उत्पादन का मूल्य	**चालू बाज़ार भावों पर, करोड़ रुपये 228544**
पशुधन उत्पादन का मूल्य	78683
कृषि एवं पशुधन उत्पादन मूल्य	307227
घटाइए आगतें	-59011
कुल मूल्य वृद्धि	248216
सिंचाई व्यवस्था का संचालन	5932
कृषि उत्पादन की कुल मूल्य वृद्धि	254148
घटाइए स्थिर पूँजी का उपभोग	-13073
शुद्ध मूल्य वृद्धि	**241075**

स्रोत : NAS, 1999

14.3.3 पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त विधि

यह भारतीय फैक्ट्रीज अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक इकाइयों का क्षेत्रक है। इससे सभी बड़े पैमाने के उद्योग हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इस क्षेत्रक से व्यापक गणना एवं प्रतिदर्श के रूप में जानकारी संग्रह करता है। जिसे वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) कहा जाता है। इस जानकारी के आधार पर उत्पादन का मूल्य आँका जाता है। इससे मध्यवर्ती उपभोग-अर्थात् कच्चा माल, ईंधन, बिजली सेवाएँ, आदि के व्यय और पूँजी ह्रास घटाकर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात की जाती है। उदाहरण के लिए हम 1986-87 में भारतीय पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य वृद्धि का आकलन इस प्रकार दिखा सकते हैं।

कुल उत्पादन का मूल्य	**(करोड़ रुपये) 545981**
घटाइए मध्यवर्ती लागतें	417244
कुल मूल्य वृद्धि, बैंक देयता सहित	128737
बैंक देयता अनुमान	–11901
कुल मूल्य वृद्धि	116836
घटाइए स्थिर पूँजी ह्रास	–24184
शुद्ध मूल्य वृद्धि	**92652**

स्रोत : NAS, 1999

14.3.4 निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त विधि

इस क्षेत्रक में व्यय तथा वस्तु प्रवाह विधियों का प्रयोग होता है। सारे निर्माण कार्यों को हम दो वर्गों (क) कच्चे निर्माण और (ख) पक्के निर्माणों में बाँट देते हैं।

कच्चा निर्माण कार्य सामान्यतः आस-पास से बिना खर्च किए सामग्री संग्रह कर श्रम तकनीक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ निर्माण है— जैसे झोंपड़ी बनाना या कच्चा बाड़ा तैयार करना आदि। इन कार्यों में जो कुछ थोड़ा बहुत नकद भुगतान होता है वही इस क्षेत्र में हुए खर्च का अनुमान होता है। सर्वेक्षण संगठन इस बारे में जानकारी एकत्र करता है।

पक्के निर्माण कार्यों में वस्तु प्रवाह विधि का प्रयोग होता है। शहरी क्षेत्र में महँगी निर्माण सामग्री, उपकरण तथा आधुनिक तकनीकों से होने वाले इन निर्माण कार्यों में ईंटें, सीमेण्ट इस्पात, बिजली व सैनीटरी आदि के उपकरणों व साज सामान का व्यापक प्रयोग होता है। इन सब के आँकड़े वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, सरकारी संस्थानों तथा निर्माण सामग्री विक्रेताओं से प्राप्त किए जाते हैं। मध्यवर्ती उपभोग, पूँजी ह्रास आदि घटाकर प्रत्येक उपक्षेत्रक की शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। भारत में 1986-1987 में निर्माण क्षेत्र की मूल्य वृद्धि का आकलन कुछ इस प्रकार रहा :

		करोड़ रुपये
उत्पादन का मूल्य		**123544**
(क) नवनिर्माण	100399	
(ख) मरम्मत रख-रखाव	23145	
घटाइए मध्यवर्ती उपभोग		76162
सकल मूल्य वृद्धि		47382
घटाइए स्थिर पूँजी ह्रास		–2308
शुद्ध मूल्य वृद्धि		**45074**

स्रोत : NAS, 1999

14.3.5 भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में कठिनाइयाँ

भारत में राष्ट्रीय आय के मापने में आने वाली कठिनाइयों को दो श्रेणियों में बाँटा जाता है .

(क) अवधारणागत कठिनाइयाँ तथा सांख्यिकीय कठिनाइयाँ।

अवधारणा कठिनाइयाँ

विकसित तथा अविकसित, सभी देशों में राष्ट्रीय आय लेखांकन में कुछ सैद्धांतिक समस्याओं का निराकरण जरूरी होता है। अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि आखिर राष्ट्रीय आय है क्या। इन कठिनाइयों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

- राष्ट्रीय आय की सर्वसम्मत परिभाषा का अभाव
- अन्तिम एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद
- हस्तांतरण भुगतान
- निःशुल्क सेवाएँ आदि

- टिकाऊ उपभोग वस्तुएँ आदि।

सांख्यिकीय कठिनाइयाँ

अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय आँकड़े

अक्सर उपलब्ध आँकड़े अधूरे तथा अपर्याप्त रहते हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र से तो फिर जैसे-तैसे आँकड़े मिल जाते हैं पर कृषि, कुटीर उद्योग तथा देशीय बैंकरों (महाजनों) आदि से उत्पादन की जानकारी के विषय में जो कुछ न कहा जाए वही बेहतर है। उत्पादन का असंगठित क्षेत्र को बहुत ही बिखरा हुआ भी है।

अमोद्रिक क्षेत्र की समस्या

कृषि तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन का काफी भाग वस्तु विनिमय का रूप लेता है। ऐसा उत्पादन जो बाज़ार तक पहुँचाती ही नहीं, उसकी कीमतों और परिभाषा की कोई सही जानकारी एकत्र नहीं हो पाती।

अपने उपभोग के लिए उत्पादन

भारत में आधे से ज्यादा कृषक तो मात्र अपने परिवार के लिए अनाज उगा पाते हैं। यह उत्पादन भी बाज़ार का मुँह नहीं देखता। यहाँ भी उत्पादन का मूल्य अटकल बाजी से ज्यादा कुछ नहीं होता।

अशिक्षा तथा अज्ञान

भारत की आधी से अधिक आबादी या आर्थिक इकाइयाँ अशिक्षा व अज्ञान में फँसी है। वे न अपनी आय की जानकारी रख पाते हैं और न ही खर्च का हिसाब। उन्हें स्वयं इस बारे में कुछ नहीं पता होता तो वह आँकड़े किसे और कैसे दे पाएँगे? विकसित देशों में प्रयुक्त लागत लेखांकन का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना होता।

स्पष्ट व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव

भारत में अधिकतर लोगों की आय मिली-जुली ही होती है। किसान फालतू समय में किसी न किसी दस्तकारों में या फिर छोटे उद्योग-धंधे में भी काम करते हैं। इसमें आय के मुख्य स्रोत का निर्णय कर पाना संभव नहीं होता और आय का अच्छा खासा हिस्सा राष्ट्रीय आय के लेखे में शामिल होने से छूट जाता है।

नई वस्तुओं की स्थिर कीमतों का मूल्यांकन

जब कोई वस्तु पहली बार उत्पादित होकर बाज़ार में आती है तो हम उसकी वर्तमान कीमत ही जान पाते हैं पर उनकी स्थिर कीमतों की बात ही अनुपयुक्त होती है। भारत में 1970-71 की कीमतों पर रंगीन टेलीविजन का मूल्यांकन इसीलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि उनका उस वर्ष तक उत्पादन ही नहीं शुरू हुआ था।

स्थिर पूँजी का ह्रास

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से स्थिर पूँजी की छीजन का अनुमान घटाकर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के आँकड़े प्राप्त होते हैं। परन्तु वर्ष भर के स्थिर पूँजी-अर्थात् मशीनों, भवनों आदि की छीजन का अनुमान लगा पाना सहज नहीं होता। इसी कारण इसमें कुछ न कुछ अस्पष्टता घर कर जाती है।

बोध प्रश्न 2

1) भारत का राष्ट्रीय आय में योगदान आकलित करने में उत्पादन विधि का प्रयोग किन-किन क्षेत्रकों में किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत में कृषि क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि का प्रयोग किस प्रकार होता है।

.....

.....

.....

.....

.....

3) भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में किस प्रकार की सैद्धांतिक कठिनाइयाँ आती हैं?

.....

.....

.....

.....

14.4 सारांश

इस इकाई में हमने राष्ट्रीय आय के आकलन की तीन विधियों से आपको परिचित कराया है। ये विधियाँ हैं : उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि और व्यय विधि। इन विधियों की व्याख्या करते समय जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर इन विधियों का प्रयोग करते समय ध्यान देना आवश्यक रहता है।

इस बात पर भी चर्चा की गई है कि तीनों विधियों का समंजन किस प्रकार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का वर्णन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा बनाए गए उप-क्षेत्रकों की व्याख्या भी की गई है। कृषि, पंजीकृत विनिर्माण तथा निर्माण क्षेत्रकों के उदाहरणों द्वारा आय में योगदान मापन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अन्त में, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में आने वाली सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक कठिनाइयों पर चर्चा की गई है।

14.5 शब्दावली

कर्मचारियों के प्रतिफल : उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम सेवाओं द्वारा सृजित साधन आय। इसे कार्य से प्राप्त आय भी कहते हैं। इसमें मज़दूरी वेतन, सामाजिक सुरक्षा के निमित्त रोज़गार दाता का योगदान, कमीशन तथा वस्तु भुगतान शामिल रहते हैं।

स्टॉक/भण्डार में परिवर्तन : वर्ष में अन्त एवं आरंभ में तैयार, अर्द्ध तैयार एवं कच्चे माल के भण्डार का अंतर।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (C.S.O.) : यह केन्द्रीय संगठन भारत में प्रति वार्षिक आधार पर 'राष्ट्रीय लेखा' तैयार करता है और संकलित राष्ट्रीय आय आदि समष्टि सूचक आँकड़ों का आकलन-प्रकाशन करता है।

दोहरी गणना : यदि किसी वस्तु का मूल्य एक बार अपने आप में तथा दूसरी बार उन वस्तुओं के रूप में जुड़ जाए जिनके उत्पादन में वस्तु का प्रयोग किया जाना है तो यह दोहरी गणना होगी। देश के समग्र घरेलू उत्पादन के आकलन में इस दोहरी गणना से बचना चाहिए।

मूल्यह्रास का प्रावधान : राष्ट्रीय पूँजी भण्डार के सामान्य क्षरण/छीजन की भरपाई के लिए रखी गई जमा निधि।

आन्तरिक क्षेत्रक : देश की अर्थव्यवस्था भौगोलिक अथवा राजनैतिक स्वरूप। अन्तरराष्ट्रीय जलमार्गों में हमारे जहाज एवं अन्य देशों में हमारे दूतावास भी आन्तरिक क्षेत्रक का ही अंग होते हैं।

प्रत्यक्ष कर : व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर लगने वाले वह कर जिनका भार उन्हें स्वयं ही वहन करना पड़ता है— अर्थात् जिसका भार वह किसी अन्य पर स्थानान्तरित नहीं कर पाते।

मृत्यु कर : किसी की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार में पाने वाले द्वारा देय कर।

टिकाऊ वस्तुएँ : ऐसी वस्तुएँ जिनका बारंबार प्रयोग संभव होता है—जैसे फर्नीचर, मशीन आदि।

आर्थिक संवृद्धि : किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रतिव्यक्ति आय (राष्ट्रीय आय/जनसंख्या) की वृद्धि की दर।

आर्थिक विकास : जब आर्थिक संवृद्धि का हम उन कारकों के साथ देखते हैं जिसके कारण संवृद्धि पर्याप्त कालावधि तक चलती रह पाती है। तो इसे आर्थिक विकास का नाम दिया जाता है।

आर्थिक कल्याण : अर्थव्यवस्था के समग्र कल्याण का वह अंश जो वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से जुड़ा है।

व्यय विधि : अर्थव्यवस्था की उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर सभी आर्थिक इकाइयों द्वारा किए गए व्यय का मापन।

अंतिम उत्पाद : अर्थव्यवस्था के उत्पादन का वह भाग जो निजी या सार्वजनिक अंतिम उपयोग अथवा निवेश के काम आ सके।

साधन आय : एक अर्थव्यवस्था में वर्ष भर में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भाग लेने के लिए साधन सेवाओं (श्रम, भूमि, पूँजी, उद्यम) की आपूर्ति करने वालों को दिया गया प्रतिफल।

बाज़ार कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि : किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादित माल के बाज़ार मूल्य तथा उस द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल व अन्य उत्पादकों से प्राप्त सेवाओं पर और लागत का अन्तर।

स्वयं रोज़गारियों की मिली-जुली आय : यह स्वनियोजितों की साधन आय (कर्मचारियों का पारिश्रमिक + प्रचालन अधिशेष) है।

साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि : बाज़ार भावों पर सकल मूल्य वृद्धि घटा उत्पादक इकाई द्वारा चुकाए गए अप्रत्यक्ष कर।

आय विधि : एक वर्ष में सृजित साधन आयों के योग तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि।

मध्यवर्ती आगतें : एक फर्म द्वारा अन्य फर्मों से खरीदी गई वे वस्तुएँ एवं सेवाएँ जो उसी वर्ष के उत्पादन में पूरी तरह प्रयोग में आ जाती हैं।

औद्योगिक क्षेत्र : राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आर्थिक गतिविधियों के समूह या वर्ग।

अनुमानित किराया : ऐसे भवन के संभावित किराए का अनुमान जिसमें भवन के स्वामी स्वयं रहता है।

मध्यवर्ती उपभोग : किसी उत्पादक इकाई द्वारा मध्यवर्ती आगतों का प्रयोग।

मध्यवर्ती उपभोग : किसी उत्पादक इकाई द्वारा मध्यवर्ती आगतों का प्रयोग।

विदेशों से शुद्ध साधन आय : किसी देश के निवासियों द्वारा अन्य देशों से प्राप्त साधन आय (कर्मचारियों का पारिश्रमिक, संपत्ति तथा उद्यम से आय) तथा अनिवासियों द्वारा उस देश से इन्हीं मदों में प्राप्त राशियों का अन्तर।

साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि : साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि *घटा* पूँजी ह्रास।

बाज़ार भावों पर शुद्ध मूल्य वृद्धि : साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि *जमा* शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।

ग़ैर-टिकाऊ वस्तुएँ : ऐसी चीजे जिनका एक बार ही प्रयोग हो पाता है।

शुद्ध निर्यात : किसी देश के निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य का अन्तर।

उत्पादन : वर्ष भर में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य।

स्वामी के अपने निवासाधीन मकान : ऐसे घर जिनमें उनके मालिक रहते हैं।

अपने प्रयोग के लिए उत्पादन : परिवारों या संस्थाओं द्वारा अपने प्रयोग के लिए उत्पादन।

प्रचालन अधिशेष : पूँजी के स्वामित्व और प्रबंधन से पैदा हुई। किराया, ब्याज व लाभ की मिली-जुली साधन आय।

प्राथमिक क्षेत्रक : अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें कृषि वान्यिकी, लट्ठा कटाई, मत्स्य पालन, खनन् एवं उत्खनन् शामिल है।

द्वितीयक क्षेत्रक : निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्र (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) तथा विद्युत, गैस और जल आपूर्ति।

तृतीयक क्षेत्रक : सेवा क्षेत्र, इसमें व्यापार, होटल एवं रेस्तरां, परिवहन, भण्डारण, संचार, वित्त, बीमा, आवासों का स्वामित्व, व्यावसायिक, सामुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएँ शामिल हैं।

हस्तांतरण आय : यह आय किसी साधन सेवा के प्रतिफलस्वरूप नहीं मिलती बल्कि एक आर्थिक इकाई किसी अन्य को ग़ैर आर्थिक कारणों दान-उपहार स्वरूप प्रदान करती है। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती।

14.6 कुछ उपयोगी पुस्तकें

C.S.O. : *National Account Statistics* (Latest), Ministry of Planning, Govt. of India, New Delhi

Hicks J.R. M. Mukherjee and S.K. Gosh, 1984 : *The Framework of the Indian Economy-An Introduction to Economics*, OUP, Delhi (Ch. 11, 12, 13)

C.S.O.: *National Account Statistics—Sources and Methods*, Ministry of Planning, Government of India, New Delhi April 1989.

14.7 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा दिशा-संकेत

बोध प्रश्न 1

1) (क) सकल निवेश — पूँजी का मूल्य ह्रास = शुद्ध निवेश

   ख) विदेशों से शुद्ध साधन आय – विदेशों से शुद्ध कर्मचारियों का पारिश्रमिक = विदेशों से संपत्ति एवं उद्यम से शुद्ध प्राप्ति।

   शुद्ध निर्यात = निर्यात मूल्य — आयात मूल्य

   ग) सकल राष्ट्रीय उत्पाद — मूल्यह्रास = शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

   घ) सकल घरेलू उत्पाद — मूल्यह्रास = शुद्ध घरेलू उत्पाद

2) विदेशों से शुद्ध साधन आय के घटक हैं :

   क) विदेशों से कर्मचारियों को शुद्ध पारिश्रमिक

   ख) विदेशों से संपत्ति तथा उद्यम से शुद्ध प्राप्तियाँ

ग) स्थानीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बचाकर रखे गए अवितरित लाभ।

यह शुद्ध साधन आय ऋणात्मक भी हो सकती है मगर विदेशियों को रखी मदों पर हुए भुगतान विदेशों से प्राप्ति से कम हो।

3) (क) बाज़ार भाव पर सकल घरेलू उत्पाद = बाज़ार भाव पर सकल मूल्य वृद्धि (अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयाँ द्वारा)

ख) बाज़ार भाव पर सकल घरेलू उत्पाद = कर्मचारियों का पारिश्रमिक + प्रचालन अधिशेष + स्व-नियोजितों की मिश्रित आय + शुद्ध अप्रत्यक्ष कर + विदेशों से शुद्ध साधन आय + मूल्यह्रास

ग) बाज़ार भाव पर सकल घरेलू उत्पाद = परिवारों को अन्तिम उपभोग व्यय + सरकार का अन्तिम उपभोग व्यय + सकल घरेलू पूँजी निर्माण + निर्यात आयात।

बोध प्रश्न 2

1) कृषि एवं संबंधित कार्य, मत्स्यन पालन, खनन्, उत्खनन्, एवं लट्ठा बनाना।

2) (क) : फसलों का चयन

ख) : प्रत्येक फसल का क्षेत्रफल मापना

ग) : (ख) को प्रतिहैक्टर उत्पाद से गुणा करना

घ) : (ग) को औसत कीमत से गुणा करना

ङ) : (घ) में से कृषि एवं संबंधित कार्यों की मध्यवर्तीलागतें घटाना

च) : (ङ) में सिंचाई व्यवस्था संचलन का जोड़ना।

छ) : (च) में से स्थिर पूँजी ह्रास घटाना।

ज) : (छ) में प्राप्त राशि ही कृषि क्षेत्रक में हुई मूल्य वृद्धि है।

3) अवधारणागत कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं :

क) अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय आँकड़े,

ख) अंतिम एवं मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद

ग) हस्तांतरण भुगतान

घ) निःशुल्क सेवाएँ आदि तथा

ङ) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ आदि

सांख्यिकीय कठिनाइयाँ इस प्रकार हैं :

क) अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय आँकड़े,

ख) गैर मौद्रिक क्षेत्र

ग) अपने उपभोग के लिए ही उत्पादन

घ) अशिक्षा एवं अज्ञान

ङ) अस्पष्ट व्यवसायिक वर्गीकरण

च) नए पदार्थों स्थिर कीमतों पर मूल्यांकन और

छ) स्थिर पूँजी के मूल्य ह्रास का अनुमाना आदि।